E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2024; 6(2): 105-114
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 25-05-2024
Accepted: 30-06-2024

भूपेन्द्र कुमार
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, संगठन और नि:शस्त्रीकरण केंद्र
अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान
जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत

Corresponding Author:
भूपेन्द्र कुमार
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, संगठन और नि:शस्त्रीकरण केंद्र
अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान
जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत

जलवायु परिवर्तन वार्ता और भारत: समानता का प्रश्न

भूपेन्द्र कुमार

DOI: https://doi.org/10.33545/26646021.2024.v6.i2b.373

सारांश
समाजों और सभ्यताओं का अतीत और भविष्य हमेशा जलवायु से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे हैं। भारत में, इस बात पर आम सहमति बढ़ रही है कि आक्रामक जलवायु परिवर्तन शमन वांछनीय है, हालांकि यह संबंधित बोझ को साझा करने के उपायों पर विभाजित है। इसलिए, अधिकांश विकासशील देशों की तरह, जलवायु वार्ता पर भारतीय विचार काफी हद तक नकारात्मक रहा हैं। कई अवसरों पर यह देखा गया है कि विकसित देश विकासशील देशों की मूल चिंताओं से अपना ध्यान भटकाते रहे हैं। इसलिए, यह एक गंभीर चुनौती है। यह पेपर सबसे पहले विभिन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों के मुख्य एजेंडे पर चर्चा करता है, और फिर जलवायु परिवर्तन वार्ता के संबंध में कुछ प्रमुख भारतीय चिंताओं पर चर्चा की गई है। है। समानता (इक्विटी) के मुद्दे भारत के बातचीत के एजेंडे में केंद्रीय रहे हैं, उनके प्रक्षेप पथ में भी बदलाव देखा गया है। इसे प्रस्तुत शोध में विवरण किया गया है।

कुटशब्द: जलवायु परिवर्तन, विकासशील, भारतीय विचार, समानता, जलवायु वार्ता, जलवायु समानता, जलवायु कॉन्फ्रेन्स

प्रस्तावना
पृथ्वी के निवासियों, विशेषकर मनुष्यों और इसकी सभ्यताओं और समाजों का भविष्य और अतीत हमेशा जलवायु से अभिन्न रूप से जुड़ा रहा है। जलवायु पौधों और जानवरों के वितरण, पालतू बनाने के लिए प्रजातियों की उपलब्ध संख्या, कृषि उत्पादन, मिट्टी के निर्माण और मानव रोगों की पारिस्थितिकी को गंभीर रूप से प्रभावित करती रही है। हाल के दिनों में, जलवायु परिवर्तन प्रमुख वैश्विक मुद्दों में से एक के रूप में उभरा है, और यह विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, जो बड़ी जलवायु परिवर्तनशीलता और भेदभाव का सामना कर रहा हैं, जो जलवायु परिवर्तन से बढ़े हुए जोखिमों के संपर्क में हैं (एमओएफएफ, 2009)। ओजोन परत की समस्या, जलवायु परिवर्तन और बढ़े हुए ग्रीनहाउस प्रभाव जैसी अन्य पर्यावरणीय समस्याओं के विपरीत वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के बीच लंबे समय से बहस चल रही है, लेकिन यह 1980 के दशक के अंत में ही हुआ जब

बढ़ती प्रतिकूल जलवायु के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय सहमति और समन्वित प्रयास सामने हुए है।

विकसित और विकासशील देशों के बीच जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारियों पर लंबी चर्चा हुई है। औद्योगिकीकृत देशों को मानवजनित जलवायु परिवर्तन का मुख्य ऐतिहासिक और वर्तमान कारण माना गया है। हालाँकि, विकासशील देशों के संबंध में, समस्या के लिए क्योटो प्रोटोकॉल में प्रस्तावित की तुलना में अधिक व्यापक तरीके से जलवायु परिवर्तन के निहितार्थों की समग्र समझ की आवश्यकता है। विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की समस्या से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तेजी से विकास करने की आवश्यकता है क्योंकि उन पर पर्यावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित होने की अधिक संभावना है। इसलिए, विकासशील देशों पर अनिवार्य बोझ डालने से उनके चल रहे विकास पथ में कमी आएगी। दिसंबर 2015 में पेरिस सम्मेलन ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने प्रयासों को निर्धारित करने की अनुमति देकर उनकी दुविधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है।

भारत में, इस बात पर आम सहमति बढ़ रही है कि आक्रामक जलवायु परिवर्तन शमन वांछनीय है, हालांकि यह संबंधित बोझ को साझा करने के उपायों पर विभाजित है। इसलिए, अधिकांश विकासशील देशों की तरह, जलवायु वार्ता पर भारतीय विचार काफी हद तक नकारात्मक रहा हैं (जोशी और पटेल, 2009)। कई अवसरों पर यह देखा गया है कि विकसित देश विकासशील देशों की मूल चिंताओं से अपना ध्यान भटकाते रहे हैं। इसलिए, यह एक गंभीर चुनौती है। यह पेपर सबसे पहले विभिन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों के मुख्य एजेंडे पर चर्चा करता है, और फिर जलवायु परिवर्तन वार्ता के संबंध में कुछ प्रमुख भारतीय चिंताओं पर चर्चा की गई है। डरबन सम्मेलन के नतीजों पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जिसने बाली मे हुए बार्ता को कमजोर कर दिया था और दीर्घकालिक सहकारी कार्रवाई (एलसीए) को "उन्नत कार्रवाई के लिए डरबन प्लेटफार्म" से बदलने के फैसले और इसके नतीजे पर भी ध्यान केंद्रित किया है।

पेरिस में 21वीं सीओपी बैठक में, संधि ने आम सम्मेलन से संबंधित विकसित और विकासशील देशों के बीच विभाजन रेखा को समाप्त कर दिया और इसे एक सामान्य ढांचे से बदल दिया, जिसका उद्देश्य सभी पक्षों को मुकाबला करने के अपने प्रयासों को मजबूत करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों और रणनीतियों को आगे बढ़ाना था। भारत ने पेरिस बैठक में बातचीत के नतीजे को एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा है।

क्योटो प्रोटोकॉल से परे

यूएनएफसीसीसी के तहत 'सहमत परिणाम' पर काम करने के लिए दूसरा वार्ता ट्रैक बाली एक्शन प्लान द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसे दीर्घकालिक सहकारी कार्रवाई (एडब्ल्यूजी-एलसीए) पर तदर्थ कार्य समूह के रूप में जाना जाता था। बाली एक्शन प्लान में, भविष्य की विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयां प्रस्तावित की गई हैं (यूएनएफसीसी 2007)। पहला प्रस्ताव भविष्य में सहमत प्रतिशत कटौती (यूएनडीपी, 2008) के लिए आधार वर्ष के रूप में 1990 का उपयोग करते हुए क्योटो-शैली के निर्धारित लक्ष्य थे। यह दृष्टिकोण औद्योगिक देशों के लिए था। दूसरा प्रस्ताव प्रति व्यक्ति पात्रता दृष्टिकोण से संबंधित था और तीसरा ब्राजीलियाई प्रस्ताव से संबंधित था जो व्यक्तिगत देशों में परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक जिम्मेदारी पर बोझ-साझाकरण दृष्टिकोण को आधार बनाता है (यूएनडीपी, 2008)। तीसरा दृष्टिकोण उत्सर्जन तीव्रता दृष्टिकोण से संबंधित था, जिसके लिए आर्थिक उत्पादन के सापेक्ष उत्सर्जन में कमी की आवश्यकता होती है; चौथा दृष्टिकोण सतत विकास नीतियों और उपायों (एसडी-पीएएम) से संबंधित था; यह दृष्टिकोण बताता है कि विकासशील देश स्वयं सतत विकास पथों का पालन करते हैं और वित्तीय सहायता के साथ इन्हें लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और पांचवां दृष्टिकोण

कार्बन विकास तंत्र (यूएनडीपी, 2008) के विकास से संबंधित था। अगला दृष्टिकोण ग्लोबल ट्रिप्टिच से संबंधित था, जो तीन क्षेत्रों पर केंद्रित है - बिजली उत्पादन, ऊर्जा-गहन उद्योग और घरेलू क्षेत्र।

यह दृष्टिकोण पहले से ही यूरोपीय संघ (ईयू) (यूएनडीपी, 2008) के भीतर इस्तेमाल किया गया था। अंत में, इसने सेक्टर-आधारित सीडीएम और ट्रिप्टिच जैसे उत्सर्जन में कमी के लिए एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण को संभव बनाया। जलवायु परिवर्तन पर बहस के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में विकासशील देशों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त शमन कार्रवाई (एनएएमए), वित्तीय मुद्दे, अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन के लिए एक प्रणाली शामिल है।

इसके बाद, 2012 के बाद की अवधि के लिए समझौते के स्वरूप के बारे में कई बहसों में दो प्रश्न शामिल थे: यानी कि क्या इसे एक दोहरे उपकरण का रूप लेना चाहिए या नहीं, यानी यूएनएफसीसीसी के तहत क्योटो प्रोटोकॉल और बाली एक्शन प्लान वार्ता या यह बस होगा एक ट्रैक बातचीत का पालन करें. इस मुद्दे पर देशों के बीच मतभेद थे; विकसित देश आम तौर पर एक ही उपकरण रखना पसंद करते थे, और विकासशील देश दो उपकरण रखना पसंद करते थे। इस मुद्दे पर कोपेनहेगन और कैनकन के निम्नलिखित सम्मेलनों में जोरदार बहस हुई। हालाँकि, 2012 में डरबन सम्मेलन में एक सफलता मिली जिसने 'दीर्घकालिक सहकारी कार्रवाई' (एलसीए) को 'डरबन प्लेटफ़ॉर्म फॉर एन्हांस्ड एक्शन' से बदल दिया था (यूएनएफसीसीसी 2012)।

कोपेनहेगन से पेरिस

कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009 और कैनकन में पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी 16) के परिणामों पर एलसीए के तहत बातचीत की गई थी। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोपेनहेगन अपेक्षाओं के वांछित स्तर तक पहुँचने में विफल रहा है क्योंकि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी कटौती के साथ नहीं आ सका था। यहां तक कि इसने विकासशील देशों और विकसित देशों के बीच मतभेदों को बनाए रखने में बाली में प्राप्त लाभ को कम कर दिया है, हालांकि इसने यूएनएफसीसी के मूल सिद्धांतों को दोहराया है जिसमें राष्ट्रों ने 'समानता' के आधार पर और 'साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के अनुसार जलवायु परिवर्तन से निपटने का वादा किया था। ' (सीबीडीआर)। चूंकि कोपेनहेगन अपेक्षित परिणाम नहीं दे सका, फिर भी, कई तकनीकी मुद्दों पर, इसने एमआरवी, एनएएमए, आरईडीडी-प्लस, अनुकूलन इत्यादि जैसी प्रगति हासिल की है।

डरबन में 17वीं COP बैठक में, इसने LCA के वार्ता ट्रैक को 'डरबन प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर एन्हांस्ड एक्शन' से बदल दिया गया था (UNFCCC, 2012)। भारत में, कई समाचार पत्रों ने बताया कि यह सीबीडीआर के मूलभूत इक्विटी सिद्धांत (सेनगुप्ता, 2012) का एक संक्षिप्त संदर्भ देने में भी विफलता को दर्शाता है (सेनगुप्ता, 2012)। 17वीं सीओपी का परिणाम 'सभी देशों द्वारा व्यापक संभव सहयोग' के अनुरूप नहीं रहा, जो स्वयं पश्चिम का सूत्रीकरण रहा है (यूएनएफसीसीसी, 1992)। इसने 'प्रोटोकॉल' को एक अन्य कानूनी उपकरण या 2015 तक कानूनी बल के साथ एक सहमत परिणाम विकसित करने के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू की थी , जिसे 'सभी पक्षों के लिए लागू' होना था और 2020 से लागू किया जाना था (बोडांस्की और राजमणि, 2013).

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डरबन में जो निर्णय अपनाया गया है वह अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ता के पूरे 20 साल के इतिहास में पहली बार था, जिसमें सीबीडीआर सिद्धांत से जुड़े 'इक्विटी' मुद्दे का एक बार उल्लेख भी नहीं किया गया था। इसने निश्चित रूप से नई दिल्ली में नीति निर्माताओं के लिए एक गंभीर चुनौती पेश की है (सेनगुप्ता, 2012)। डरबन सम्मेलन के बाद, दोहा में 18वीं सीओपी बैठक आयोजित की गई, जिसमें 'दोहा गेटवे' को अपनाने के साथ बातचीत में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जो उन्नत कार्रवाई के लिए डरबन प्लेटफार्म के तहत स्थापित रोडमैप को

प्राप्त करने के लिए तैयार हुआ (यूएनएफसीसीसी 2013)। इस सीओपी का समग्र परिणाम उत्सर्जन में कटौती से संबंधित नुकसान और क्षति के भुगतान से संबंधित मध्यावधि प्रतिबद्धताओं और प्रस्तावों से संबंधित है (मेनन, 2012)।

COP19 2013 में वारसॉ में हुआ; इस बैठक ने जलवायु समझौते की बुनियादी नींव रखी, जिस पर 2015 में पेरिस में हस्ताक्षर किए जाने थे; इस बैठक में विकासशील और विकसित देशों के बीच बोझ साझा करने पर बहस जारी रही और बैठक में ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के अपने संकल्प की पुष्टि की गई। लीमा में COP20 ने आगामी पेरिस संधि को अंतिम रूप देने की तैयारी की। इसने सामान्य नियमों का भी अनावरण किया जिन पर अगले वर्ष हस्ताक्षर किए जाने थे, इसमें 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) (मेनन, 2014) शामिल थे (मेनन, 2014)।

अंततः, पेरिस में 21वीं सीओपी बैठक एक नई संधि के साथ सामने आई जो कथित तौर पर विकसित और विकासशील देशों के बीच सख्त भेदभाव को समाप्त करती है। इसने एक साझा ढांचा तैयार किया जिसके तहत सभी देशों को अपने सर्वोत्तम प्रयास करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पड़ी। पहली बार यह आवश्यक हुआ कि सभी पक्षों को अपने उत्सर्जन और कार्यान्वयन प्रयासों पर नियमित रूप से रिपोर्ट करनी होगी, जो एक सहमत अंतरराष्ट्रीय समीक्षा से गुजरेगी।

जलवायु परिवर्तन वार्ता पर भारत

भारत के लिए, जलवायु परिवर्तन विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह भारत की विकास प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी डालता है। इसके अलावा, भारत मै तेजी से हो रहे शहरीकरण, औद्योगीकरण, इसके आर्थिक विकास को प्रभावित करता रहा है। प्रतिकूल वायुमंडलीय स्थितियों के मद्देनजर भारत में जल संसाधन, जैव विविधता, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि उत्पादकता जैसे विभिन्न क्षेत्रों को सीधे तौर पर खतरा होगा। जलवायु परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों जैसे पानी, वर्षा, जैव विविधता, स्वास्थ्य और चरम घटनाओं जैसे गर्म दिनों की बढ़ती आवृत्ति, गर्मी की लहरें, सूखा, घटते जल स्तर, फसल विफलता आदि को प्रभावित करेगा। इसलिए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे भारत के लिए विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि इसमें विकास, भेद्यता और विकास की एक जटिल परस्पर क्रिया शामिल है; इस प्रकार, जलवायु मुद्दों पर बातचीत एक बहुत ही प्रासंगिक विषय रहा है, और आगे बढ़ते हुए, इसमें भारत के लिए रणनीतिक महत्व भी शामिल है।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर अपनी पूरी इच्छा व्यक्त की है। हालाँकि, भारत के आधिकारिक रुख में कहा गया है कि इक्विटी मुद्दों को संबोधित किए बिना कोई भी बातचीत संभव नहीं थी, जो औद्योगिक देशों द्वारा गरीब देशों पर रखे गए ऐतिहासिक बोझ से उभरे हैं, जो न केवल मानवजनित जीएचजी के मौजूदा स्टॉक में मुख्य योगदानकर्ता रहे हैं, बल्कि जारी भी हैं। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भारत जैसे गरीब देश से कई गुना अधिक है (एमओएफएफ 2009 और कपूर, 2009)।

इसके अलावा, भारत की आधिकारिक स्थिति ने अनुबंध 1 के तहत विकसित देशों द्वारा प्रतिबद्धता की कमी को उजागर किया है। अन्य विकसित देशों की तुलना में भारतीयों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन पहले से ही बेहद कम है। इसके अलावा, भारत ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली अपनी कमजोरियों को कम करने के लिए घरेलू स्तर पर कई कदम उठाए हैं। भारत पर अक्सर पश्चिम द्वारा जलवायु परिवर्तन के मुद्दों और अपने हितों की रक्षा के संबंध में जोरदार रुख अपनाने का आरोप लगाया जाता रहा है और इसे अक्सर नकारात्मक रवैये के रूप में चित्रित किया गया है। हालाँकि, यह पश्चिम था, जिसने अभी तक यह प्रदर्शित नहीं किया है कि वह जलवायु परिवर्तन के बारे में गंभीर है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका का रवैया शुरू से ही बहुत

ही उदासीन रहा है; इसने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसी तरह, अमेरिकन रष्ट्रपति ट्रम्प ने पेरिस जलवायु समझौते से भी खुद को अलग कर लिया था।हालाँकि अमेरिकन रष्ट्रपति जो बाइडन ने वापस पेरिस समझौते मै शमिल हो गये। भारत ने स्पष्ट किया कि वह अनुकूलन और शमन के लिए भुगतान नहीं करेगा, और इसे (हकदार) संसाधन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से व्यवहार्य बनाना होगा। भारत की आधिकारिक स्थिति इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन का दीर्घकालिक अभिसरण "जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक समझौते के लिए एकमात्र न्यायसंगत आधार है" (एमओएफएफ 2009 और पटेल और जोशी 2009)।

जलवायु परिवर्तन वार्ता की शुरुआत से ही भारतीय रुख में कहा गया था कि किसी भी स्थिरीकरण लक्ष्य को इस सिद्धांत के आधार पर हासिल किया जाना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य को सामान्य वायुमंडलीय संसाधनों पर समान अधिकार है, जिसमें एकाग्रता को जमा करने में विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी भी शामिल होनी चाहिए। वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसें (MOFF 2009)। विकास और जलवायु परिवर्तन के साथ इसके संबंधों के मुद्दे पर, यह अच्छी तरह से माना गया है कि भारत अभी भी विकसित दुनिया की तुलना में मानव विकास सूचकांक के कई संकेतकों पर बहुत पीछे है। इसलिए, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में तेजी से विकास और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए क्षमता निर्माण की भी आवश्यकता है।

जलवायु परिवर्तन वार्ता में मूलभूत मुद्दों में से एक उत्सर्जन लक्ष्य रहा है, जो वास्तविक रूप से समस्या की भयावहता पर विचार करेगा और तदनुसार, इस पर अंतरराष्ट्रीय सहमति विकसित करेगा। निश्चित रूप से, इसे एक न्यायसंगत प्रतिमान के तहत एक समय सीमा के भीतर काम करना होगा जहां विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए कार्बन स्पेस साझा करना भी उचित होगा। इसे विकसित देशों के ऐतिहासिक बोझ पर भी विचार करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थिरीकरण लक्ष्य समानता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए।

मापने योग्य, रिपोर्ट करने योग्य और सत्यापन योग्य (एमआरवी) शमन कार्रवाइयों के मुद्दे पर, भारत ने पहले व्यक्त किया था कि विकासशील देशों को विकसित देशों से वित्तीय और तकनीकी सहायता के अभाव में मापने योग्य, रिपोर्ट करने योग्य और सत्यापन योग्य शमन कार्रवाइयों को लागू करने के लिए एक नई प्रतिबद्धता नहीं अपनानी चाहिए (एमओएफएफ 2009)। विकासशील देशों के संदर्भ में, एमआरवी संविदात्मक व्यवस्था लागू करता है जिसके तहत उन्हें शमन को कम करने के लिए वित्तीय, तकनीकी और अन्य क्षमता-निर्माण सहायता प्राप्त होती है; इसके अलावा, भारत ने पहले सुझाव दिया था कि विकासशील देश, स्वैच्छिक आधार पर, शमन कार्यों का प्रस्ताव कर सकते हैं जिन्हें वे लागू करने की पेशकश करते हैं, बशर्ते कि सहमत पूर्ण वित्तीय और तकनीकी बोझ विकसित देशों द्वारा सहमत वित्तीय तंत्र (एमओएफएफ 2009) के माध्यम से पूरा किया जाए।

राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त शमन कार्रवाई (एनएएमए) के मुद्दे पर, बाली एक्शन प्लान में मापने योग्य, रिपोर्ट करने योग्य और सत्यापन योग्य, प्रौद्योगिकी, वित्तपोषण और क्षमता निर्माण द्वारा समर्थित और सक्षम टिकाऊ विकास के संदर्भ में विकासशील दलों द्वारा एनएएमए पर विचार करने की परिकल्पना की गई है (एमओएफएफ 2009)। हालाँकि, भारत का सुझाव है कि विकासशील देश पार्टियाँ सीबीडीआर और आरसी (एमओएफएफ 2009) के सिद्धांत के अनुसार NAMAs के माध्यम से अपने शमन कार्यों को बढ़ा सकते हैं। ये कार्रवाइयां राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और सतत विकास और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में होनी चाहिए। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित और तैयार किया जाएगा (एमओएफएफ 2009)।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अनुकूलन और शमन दोनों यूएनएफसीसीसी का समान रूप से अभिन्न अंग रहे हैं। अनुकूलन पर बढ़ी हुई कार्रवाई के मुद्दे पर, यूएनएफसीसीसी योजना और कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की पहचान करता है; जोखिम प्रबंधन और कटौती, जिसमें बीमा और आपदा न्यूनीकरण रणनीतियाँ शामिल हैं; आर्थिक विविधीकरण; और विकासशील देशों में अन्य संस्थाओं द्वारा कार्रवाई को बढ़ाने और एकीकृत करने में सम्मेलन की उत्प्रेरक भूमिका को मजबूत करना जो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, एलडीसी और एसआईडीएस (एमओएफएफ 2009) के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं।

अनुकूलन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से धन जुटाने का आह्वान किया गया। इसके लिए, अनुकूलन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए COP7 और अन्य COPs के तहत तीन नए फंड स्थापित किए गए है। अनुकूलन पर सहायता के अठारह क्षेत्रों की पहचान की गई, जिसमें जीईएफ फंडिंग भी शामिल है, और एलडीसी के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कार्यक्रम (एनएपीए) के विकास की प्रक्रिया भी सीओपी7 (यूएनएफसीसीसी 2002-03) के तहत हासिल की गई थी। भारत ने सुझाव दिया कि अनुकूलन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए एक व्यापक और लचीले ढांचे की आवश्यकता है जो अनुकूलन योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन, लचीलेपन का निर्माण और उचित वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ जोखिमों को कम करने और प्रबंधित करने में मदद करेगा (एमओएफएफ 2009) और राय और डेविड विक्टर 2009)।

इसलिए, यह जरूरी है कि समानता सिद्धांत, लैंगिक संवेदनशीलता और संस्थागत तंत्र के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की स्थापना को ध्यान में रखते हुए अनुकूलन का पालन किया जाना चाहिए, खासकर विकासशील देशों और भारत के संबंध। चूंकि इन सार्वजनिक वस्तुओं को वितरित करने और वित्तपोषण के लिए वर्तमान वैश्विक वास्तुकला को जलवायु परिवर्तन पर बहुपक्षीय बातचीत वाले संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के तहत अनिवार्य किया गया है, भारत ने इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय संसाधनों को नया और अतिरिक्त होना होगा। इसे विदेशी विकास सहायक (ओडीए) और अन्य शुद्ध विदेशी प्रवाह के माध्यम से पारित नहीं किया जाना चाहिए; इसके अलावा, इसने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावित फंडिंग स्रोत धन के स्वैच्छिक प्रदाता नहीं हो सकते हैं क्योंकि स्वैच्छिक योगदान पूर्वानुमानित नहीं हैं और कानूनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं (एमओएफएफ 2009)।

यूएनएफसीसीसी के तहत उन्नत शमन और अनुकूलन के लिए सभी पक्षों के बीच पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास, तैनाती, अपनाने, प्रसार और हस्तांतरण में तेजी लाने की आवश्यकता है। इसलिए, विकास प्रक्रिया में अनुकूलन के एकीकरण और स्टैंड-अलोन अनुकूलन गतिविधियों (एमओएफएफ 2009)। सीमित वित्तपोषण के कारण, गैर-अनुलग्नक I पार्टियों को प्रौद्योगिकी विकास, तैनाती, प्रसार और हस्तांतरण प्रदान करना अनिवार्य है। इसलिए, प्रौद्योगिकियों तक पहुंच अत्यावश्यक है, जबकि संयुक्त रूप से विकसित प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) साझाकरण (एमओएफएफ 2009) सहित मानव जाति के सामान्य हित के साथ नवप्रवर्तकों के लिए पुरस्कारों को संतुलित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

जहां तक मौजूदा संस्थागत व्यवस्थाओं का सवाल है, ये विकासशील देशों और देशों के अन्य कमजोर समूहों को तत्काल और तत्काल प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण लाने के लिए अपर्याप्त हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए मौजूदा तंत्र में सुधार करना होगा। यह प्रौद्योगिकी और संबंधित वित्त और क्षमता निर्माण (एमओएफएफ 2009) पर कन्वेंशन दायित्वों की डिलीवरी को बढ़ाने का साधन प्रदान करेगा। अंत में, उत्सर्जन व्यापार और परियोजना-आधारित तंत्र के मुद्दे

पर, भारत ने इस बात पर जोर दिया कि नवीकरणीय ऊर्जा स्वच्छ विकास तंत्र गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

डरबन सम्मेलन के नतीजे पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से यह प्रतिबिंबित हुआ कि जलवायु परिवर्तन वार्ता अपेक्षाकृत नए और अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। इसलिए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना होगा। नवरोज के दुबाश ने तर्क दिया कि भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी आबादी के उच्च गरीबी स्तर के विकास और आवंटन की संभावनाओं को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, और दूसरी बात, भारत को एक प्रभावी वैश्विक जलवायु प्रतिक्रिया में भी गहरी रुचि है (दुबाश, 2012)।

सीबीडीआर सिद्धांत को मान्यता देने में डरबन प्लेटफ़ॉर्म की विफलता ने भारत को जलवायु समानता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जलवायु समानता पर भारत के रुख को पुनर्संकल्पित करने से संबंधित है, विशेष रूप से छोटे द्वीपों और अल्प विकसित देशों के समूह की चिंताओं के संबंध में। जलवायु समानता के लिए एक पुनर्निर्मित दृष्टिकोण में किसी कार्य के लिए ज़िम्मेदारी या दोषीता और प्रतिक्रिया देने की ज़िम्मेदारी या कर्तव्य के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर शामिल होना चाहिए।

उपरोक्त चर्चाओं में चल रही जलवायु परिवर्तन वार्ताओं पर भारत की मुख्य आपत्तियों को संक्षेप में दर्शाया गया है। भारत के वार्ताकार बदलती प्रकृति, जलवायु परिवर्तन, राजनीति के प्रति सदैव सचेत रहे हैं। हालाँकि, इसने जलवायु परिवर्तन वार्ताओं के प्रति लचीला रवैया दिखाया है। समानता के मुद्दे जो भारत के बातचीत के एजेंडे में केंद्रीय रहे हैं, उनके प्रक्षेप पथ में भी बदलाव देखा गया है। पहले, इक्विटी मुद्दों में मुख्य रूप से सीबीडीआर सिद्धांत शामिल था, लेकिन बाद में, यह संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के साथ सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों में विकसित हो गया है।

यह संयुक्त राज्य अमेरिका के आग्रह पर कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ, जिसने बाद में डरबन सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन पर बातचीत की दिशा ही बदल दी। विकासशील देशों के लिए अनिवार्य उत्सर्जन कटौती को दूर करने के भारत के लगातार प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिले; अंतिम पेरिस जलवायु समझौते में विकासशील देशों के लिए ग्रीनहाउस गैसों को कम करने के लिए स्वैच्छिक प्रतिज्ञा की गई है।

इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के लिए अपने प्रयासों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। इसने जलवायु परिवर्तन में क्षेत्रीय सहयोग को नई गति दी है। SARRC ने जलवायु परिवर्तन पर सहयोग को अपनी साझेदारी के एक प्रमुख परिभाषित विषय के रूप में अपनाया है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन वाले देशों के बेसिक समूह के भागीदार के रूप में, सामूहिक कार्रवाई के क्षेत्रों को शामिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वार्ता से परे इस मुद्दे पर काम कर रहा है। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया कि वह अंतरराष्ट्रीय वार्ता में सक्रिय रूप से शामिल होना जारी रखेगा, यहां तक कि जहां उचित हो वहां 'डील मेकर' की भूमिका भी निभाएगा, वह कार्रवाई करने के लिए इंतजार नहीं करेगा।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने संकल्प को दर्शाते हुए, भारत जलवायु परिवर्तन पर अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) लेकर आया है, जो जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए भारत की रणनीति का रोडमैप प्रदान करता है। पेरिस डील में, भारत सरकार के अधिकारियों ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की क्योंकि सौदे के दो प्रमुख उद्देश्य थे: पहला, सीबीडीआर सिद्धांत को कायम रखना और दूसरा, विकासशील और विकसित देशों के बीच मतभेदों को स्वीकार करना। इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित

योगदान (आईएनडीसी) के सवाल पर, हालांकि सरकार इसे तार्किक परिणाम के रूप में देखती है, लेकिन उनके संबंधित खंड, जैसे पांच साल की समीक्षा, को गंभीरता से लेने की जरूरत है।

एक अन्य मुद्दा जिसका पेरिस समझौते में उल्लेख नहीं किया गया है वह ऐतिहासिक जिम्मेदारियों के खंड से संबंधित है जिसका संधि के अंतिम परिणाम में उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा, इस सौदे में जानबूझकर पांचवीं रिपोर्ट मूल्यांकन रिपोर्ट की उपेक्षा की गई है, और इसने एक महत्वाकांक्षी सौदा तय किया है। इससे उन विकासशील देशों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी जिनका कार्बन स्पेस पहले ही काफी कम हो चुका है (मीनाक्ष, 2016)।

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत करना कठिन है क्योंकि इसमें न्याय और समानता जैसे विभिन्न मानक आयाम शामिल हैं। विकासशील और विकसित दोनों देशों के लिए अपने सख्त रुख में ढील देना जरूरी है क्योंकि वैश्विक सुरक्षा खतरे इस मुद्दे को सुलझाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते है। विकसित दुनिया के लिए यह आवश्यक है कि वे इस दिशा का नेतृत्व करें। विकसित देशों को वैश्विक सुरक्षा मुद्दों को शून्य-योग परिणाम के तौर नहीं देखना चाहिए, और उन्हें लचीला दृष्टिकोण अपनाने चाहिए जिसमें विकासशील देशों की चिंताओं को भी शामिल किया जा सके।

व्यापार, वित्त, सुरक्षा, गरीबी आदि जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के विपरीत, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे प्रकृति में जटिल हैं क्योंकि यह विज्ञान में निहित हैं। वैज्ञानिक भविष्यवाणी में कोई भी गलती जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को नष्ट कर देती है। आईपीसीसी रिपोर्ट 2007 में भविष्यवाणी की गई थी कि हिमालय के ग्लेशियर 2030 तक पूरी तरह पिघल जाएंगे; हालाँकि, यह रिपोर्ट झूठी प्रतीत हुई (कपूर एट अल., 2009)। इसलिए, यह आवश्यक हो गया है कि विकासशील देशों को खुली और गुप्त रणनीति में नहीं फंसना चाहिए जो अरबों डॉलर के पर्यावरणीय व्यवसायों को आगे बढ़ा सकता है और ऋण जाल में फंस सकता है। भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों को मौलिक अनुसंधान को बढ़ावा देना आवश्यक है।

अनेक COPs सम्मेलनों के नतीजे ने इक्विटी मुद्दों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत की विफलता को उजागर किया। यह उसके गठबंधन प्रबंधन की बुद्धिमत्ता पर एक गंभीर सवाल उठाता है। इसलिए, यदि आने वाले दशक में एक अरब से अधिक भारतीयों के हितों को पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जाना है, तो यह जरूरी है कि भारत को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक सुसंगत और भव्य रणनीति विकसित करनी चाहिए जिसे व्यापक समर्थन प्राप्त हो (सेनगुप्ता, 2012)। भारत ने इस बात की वकालत की है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के किसी भी प्रयास से सह-लाभ होना चाहिए, यानी कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास विकास के अनुरूप होना चाहिए।

प्रफुल्ल बिदवई ने कहा कि समानता के मुद्दों पर भारतीय दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि यह न केवल विकास संबंधी चिंताओं को बल्कि पर्यावरण संबंधी चिंताओं को भी प्रतिबिंबित कर सके (बिदवई, 2012)। वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत करना, जैसे कि जलवायु परिवर्तन पर एक सर्वमान्य वैश्विक संधि, वैश्विक समुदाय के लिए एक कठिन चुनौती साबित हुई, जैसा कि जलवायु परिवर्तन वार्ता के इतिहास में देखा गया है। पेरिस समझौता स्पष्ट करता है कि लगातार प्रयास से अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। भारत के लिए पेरिस समझौते का अंतिम नतीजा अनुकूल नजर आया. हालाँकि, उसे आईएनडीसी में किसी भी हस्तक्षेप को लेकर सतर्क रहना चाहिए।

संदर्भ

1. बिदवई, पी. (2012)। जलवायु परिवर्तन की राजनीति और वैश्विक संकट: हमारा भविष्य

गिरवी रखना, नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड।

2. बोडांस्की और राजमणि (2013)। इवोल्यूशन एंड गवर्नेंस आर्किटेक्चर ड्राफ्ट: 28 अक्टूबर, 2012, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक जलवायु परिवर्तन में आगामी, संस्करण। डेटलेफस्प्रिन्ज़ और उर्स ल्यूटरबैकर द्वारा (दूसरा संस्करण, एमआईटी प्रेस)।, [ऑनलाइन: वेब] 15 मार्च 2016 को एक्सेस किया गया, यूआरएल: http://ssrn.com/abstract=2168859।
3. दुबाश, एन. (सं.). (2012)। जलवायु परिवर्तन और भारत की पुस्तिका: विकास, राजनीति और शासन। नई दिल्ली: रूटलेज.
4. जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (2007), जलवायु परिवर्तन 2007 शमन: जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट में कार्य समूह III का योगदान, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस: न्यूयॉर्क।
5. जोशी, वी. और उर्जित पटेल (2009)। इंडिया एंड ए कार्बन डील, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 51(2): 71-77।
6. कपूर, डी., खोसला, आर., और मेहता, पी.बी. (2009)। जलवायु परिवर्तन: भारत के विकल्प। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 44(31):34-42
7. माज़ो, जे. (2009). जलवायु संघर्ष: ग्लोबल वार्मिंग से सुरक्षा को कैसे खतरा है और इसके बारे में क्या करना है, आईआईएसएस: रूटलेज।
8. मेनन, एम. (2012)। दोहा दौर "नॉट सो परफेक्ट" निष्कर्ष की ओर बढ़ता है, द हिंदू, 08 दिसंबर।
9. मेनन, एम. (2014)। लीमा, क्लाइमेट एक्शन के लिए एक नया निम्न, द हिंदू, 22 दिसंबर।
10. एमओएफएफ (2009), जलवायु परिवर्तन वार्ता: जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए भारत का प्रस्तुतीकरण, अगस्त, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. पेरिस समझौता (2015)। पेरिस समझौते को अपनाना, [ऑनलाइन: वेब] 10 मार्च 2016 को एक्सेस किया गया, यूआरएल https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
12. राय, वी., और विक्टर, डी.जी. (2009)। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा चुनौती: भारत के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 44(31): 78-85।
13. राजमणि, एल. (2011)। "डीकंस्ट्रक्टिंग डरबन", इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, 15 दिसंबर।
14. रमन, एम. (2016)। पेरिस में जलवायु परिवर्तन की लड़ाई, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 51(2):35-40।
15. रिचर्ड्स, केनेथ एट अल। (2011). अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ता: मुख्य सबक और अगले कदम, स्मिथ स्कूल ऑफ एंटरप्राइज एंड द एनवायरनमेंट, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय।
16. सेनगुप्ता, एस. (2012)। डरबन सम्मेलन से सबक, द हिंदू, 14 फरवरी।
17. सिन्हा, यू.के. (2011)। भारत और जलवायु परिवर्तन, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पुस्तिका, डेविड स्कॉट द्वारा संपादित, नई दिल्ली: रूटलेज।
18. यूएनडीपी (2008), बाली रोड मैप: बातचीत के तहत प्रमुख मुद्दे, यूएनडीपी, पर्यावरण और ऊर्जा समूह, [ऑनलाइन: वेब] मार्च 15,2016 तक पहुंच, यूआरएल: http://undpcc.org/docs/Bali%20Road%20Map/English/ बाली_रोड_मैप_मुख्य_मुद्दे_अंडर_नेगोशिएशन.pdf।
19. यूएनडीपी (2008), फाइटिंग क्लाइमेट चेंज: ह्यूमन सॉलिडैरिटी इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। मानव

विकास रिपोर्ट 2007-8, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।

20. यूएनईपी (2005), वाइटल क्लाइमेट चेंज ग्राफिक्स। [ऑनलाइन: वेब] 31 जुलाई 2014 को एक्सेस किया गया, यूआरएल: http://www.grida.no/publications/vg/climate2/।
21. यूएनएफसीसी (2013), 26 नवंबर से 08 दिसंबर 2012 तक दोहा में आयोजित इसके अठारहवें सत्र पर पार्टियों के सम्मेलन की रिपोर्ट, [ऑनलाइन: वेब] 06 अप्रैल 2016 को एक्सेस किया गया, यूआरएल: http://unfccc.int/resource /docs/2012/cop18/eng/08a01.pdf#page=3.
22. यूएनएफसीसीसी (2012), 26 नवंबर से 08 दिसंबर 2012 तक दोहा में आयोजित इसके अठारहवें सत्र पर पार्टियों के सम्मेलन की रिपोर्ट, यूएनएफसीसीसी/सीपी/2012/एडीडी.1। [ऑनलाइन: वेब] 15 मार्च 2016 को एक्सेस किया गया, यूआरएल: https://unfccc.int/resource/docs/2012/cop18/eng/08a01.pdf।
23. यूएनएफसीसीसी (2002), 29 अक्टूबर से 10 नवंबर 2001 तक मराकेश में आयोजित अपने सातवें सत्र पर पार्टियों के सम्मेलन की रिपोर्ट, यूएनएफसीसीसी/सीपी/2001/13Add.1, [ऑनलाइन: वेब] 15 मार्च 2016 को एक्सेस किया गया, यूआरएल : https://unfccc.int/resource/docs/cop7/13a01.pdf।
24. यूएनएफसीसीसी (2013), वारसॉ में 11 से 23 नवंबर 2013 तक आयोजित अपने उन्नीसवें सत्र पर पार्टियों के सम्मेलन की रिपोर्ट, यूएनएफसीसीसी/सीपी/2013/10, [ऑनलाइन: वेब] मार्च 15,2016 तक पहुंच, यूआरएल: https://unfccc.int/resource /docs/2013/cop19/eng/10.pdf.
25. यूएनएफसीसीसी (2007), निर्णय 1/सीपी.13, 'बाली एक्शन प्लान', एफसीसीसी/सीपी/ 2007/6/एड.1 में (14 मार्च 2008)।
26. यूएनएफसीसीसी (2012), निर्णय 1/सीपी.17, 'उन्नत कार्रवाई के लिए डरबन प्लेटफॉर्म पर एक तदर्थ कार्य समूह की स्थापना, 2011', एफसीसीसी/सीपी/2011/9/एड.1 (15 मार्च 2012) में।
27. यूएनएफसीसीसी (2009), निर्णय 2/सीपी.15, 'कोपेनहेगन समझौता', एफसीसीसी/सीपी/ 2009/11/एड.1 में (30 मार्च 2010)।
28. संयुक्त राष्ट्र (1992)। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, [ऑनलाइन: वेब] 15 मार्च 2016 को एक्सेस किया गया, यूआरएल: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf।
29. संयुक्त राष्ट्र (1998)। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, [ऑनलाइन: वेब] 15 मार्च 2016 को एक्सेस किया गया, यूआरएल: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf।